

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2746
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

2746. डॉ. संबित पात्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 और 2025 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की कितनी बैठकें हुईं और उनके मुख्य परिणाम क्या रहे हैं;

(ख) बाल कुपोषण उन्मूलन, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से सरकार द्वारा क्या कोई कार्ययोजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): 1 जनवरी, 2014 से 31 जुलाई, 2025 के बीच, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की 63 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित व्यापक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है, और सहयोगात्मक भावना से ऐसे मुद्दों को सुलझाने या प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित सिफारिशों की गई हैं।

(ख): क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में बाल कुपोषण उन्मूलन, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण और पंचायतों की आय बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रगति की स्थिति के साथ-साथ चिंता के बिंदुओं और इन मुद्दों पर कार्रवाई पर भी चर्चा की गई है। तदनुसार, जनवरी 2023 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में 'पोषण अभियान के माध्यम से बालिकाओं में कुपोषण को दूर करने' के एजेंडे पर नियमित रूप से चर्चा की गई है; सहकारी आंदोलन

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 2746, दिनांक 05.08.2025

को मजबूत करने के मुद्दे पर अगस्त 2023 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में 'सहकार से समृद्धि - देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना' शीर्षक पर चर्चा की गई है; महिला सशक्तिकरण से संबंधित एजेंडा के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों में त्वरित जांच और ऐसे मामलों की समय पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर जनवरी 2022 से सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों में चर्चा की गई है; पंचायतों की आय बढ़ाने से संबंधित एजेंडा पर 24.6.2025 को आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के साथ-साथ इससे पहले इसकी स्थायी समिति में भी चर्चा की गई है।

(ग): क्षेत्रीय परिषदों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके द्वारा प्रायोजित मुद्दों पर सहयोगात्मक भावना से चर्चा करने तथा ऐसे मुद्दों के समाधान या प्रगति प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित सिफारिशें करने के लिए एक प्रभावी वैधानिक मंच उपलब्ध कराने के मद्देनजर, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या तथा उनमें चर्चा किए गए मुद्दों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।
